□□□□□□□□□□

जनसत्ता 15 मई, 2014 : जून 2003 में पोलैंड यात्रा का हमारा आखिरी प□ाव था, 'आउसवत्ज़ि यातना शविरि'□

यहां पहुंचने से पहले, सुना था कि आउसवत्ज़ि, बर्लनि स्थति जाक्सेनहाउजेन यातना शविरि से भी वीभत्स है□ वायस ऑफ जर्मनी (डॉयचे वेले) से पंद्रह दनिों के लि□ पोलैंड ग□ हम जैसे कोई पच्चीस पत्रकार वारसा, क्राकोव, गेदांस्क जैसे शहरों में जतिने आनंदति और अभभिूत थे, आउसवत्ज़ि यातना कैंप को देखने के बाद खामोश हो ग□□ आउसवत्ज़ि में कोई ग्यारह लाख यहूदयिों को त□ पा-त□ पा कर मारा गया था□ इंसान को जदिा जलाने वाली भट्ठयिां, गैस चेंबर, आउसवत्ज़ि में ही देखीं□ □क्तार में पांच सौ मर्द-औरत, □क-दूसरे से सट कर सामूहकि शौच कर सक्ते है, उसकी कल्पना हममें से कसिी ने नहीं की थी□ क्या कसिी कौम से बदला लेने की वहशत में इंसानयित सचमुच मर जाती है?

अब यूरोप वाले कह रहे है कि जलयिांवाला बाग में 379 लोगों की हत्या पर जब 'मेमोरयिल' बन सक्ता है, तो गुजरात दंगों में मारे ग□ दो हजार लोगों की याद में स्मारक क्यों नहीं बन सक्ता? सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्त का संकल्प करने वालों को शायद यह बात अच्छी न लगे□ उन्नीस सौ चौरासी में सखिों का क्त्लेआम कराने वालों को भी यह बात बुरी लग सक्ती है□ ऐसे लोगों का सोच है कि जनि्हें 'जलते टायर की माला' पहना कर मार दयिा गया, उनकी याद में स्मारक बनाने की क्या जरूरत है?

सबसे अधकि सखि, दल्लिी के त्रलिोक्पुरी में मारे ग□ थे□ तीस साल गुजर चुके□ अभी आप त्रलिोक्पुरी के गली-कूचों में घूम आइ□, दंगे का □क भी नशिान नहीं मलिेगा□ पश्चमि रेलवे के पीआरओ ने बताया कि गोधरा में साबरमती □क्सप्रेस के जले हु□ डब्बि, कब के हटा□ जा चुके है□ अमदाबाद की गुलबर्गा सोसाइटी के खंडहर दंगे की हौलनाक दास्तान कहते है□ लेकनि चमनपुरा, नानवाडा, नरोदा पाटयिा, नरोदाग्राम, सदरपुरा, हम्मितनगर, सधिी बाजार, रेव□ी बाजार बस यह बयान करने भर को रह ग□ है कि बारह साल पहले यहां दंगा हुआ था□ दंगे के नशिान शायद ही इन जगहों पर दखिें□ गुजरात दंगे पर बनी फल्मि 'परजानयिां' जरूर हमारी रूह को हलिा देती है कि अगर यही हमारे परविार के साथ हो जाता, तो हम कहीं के नहीं रहते!

यूरोप वाले दंगे, नरसंहार, इंसानी अत्याचार को क्यों पर्यटन का हस्सिा बना देते है? क्यों आउसवत्ज़ि देखने के लि□ हमें कम से कम दस यूरो (लगभग आठ सौ रुप□) खर्च करने प□ते है? क्यों न्यूयार्क में '9/11 म्यूज़यिम व मेमोरयिल' देखने के लि□ आपको चौबीस डॉलर (लगभग सा□े चौदह सौ रुप□) खर्च करने होते है? अजब अर्थशास्त्र है□ आतंकी वधि्वंस, जनसंहार के वनिाशकारी नतीजे को देखना है, तो पैसे खर्च कीजि□□ अमेरकि और यूरोप की सरकारों ने 'नरसंहार मेमोरयिल' बना रखा है□ बाजारवाद ने वधि्वंस, इंसानयित की समाप्त से भी पैसे उगाहने का गुर सखिा दयिा है□ 'आउसवत्ज़ि यातना शविरि' यूनेस्को की वशि्व वरिासत सूची में शामलि है□ क्या पश्चमि वाले गुजरात में भी दंगे का 'वशि्व स्मारक' बना हुआ देखना चाहते है? यूरोप वाले जख्म भरना चाहते है, या जख्म का टांका खोलना चाहते है?

लेकिन पिछले साल भर से नई सरकार के दावेदार नरेंद्र मोदी से जो संवाद यूरोप का चल रहा है, उससे यही लग रहा है कि 2002 दंगे की भयावह तस्वीर □क टाइम कैप्सूल (बीजकोष) में डाल दी गई है□ जब बात बिग□गी तब उस विषैले 'बीजकोष' को खोला जा□गा□ फिलहाल के लि□ तो मोदी को क्षीर पाक विधि से शुद्ध करने का काम यूरोपीय संघ ने किया है□ पिछले साल मार्च में यूरोपीय संघ ने मोदी का बहिष्कार समाप्त करने की घोषणा की□ उसके लि□ माहौल ब्रिटेन ने बनाया□ अमेरिका ने भी अपने यूरोपीय मित्रों की बात मान ली, और वहां मोदी चाय की चुस्कियां लोग लेने लगे□

मगर इससे यह भ्रम नहीं पाल लेना चाहि□ कि मानवाधिकार रक्षा का मुद्दा यूरोपीय संघ के चार्टर से गायब हो गया है□ न ही 2002 दंगों के सवाल को उन्होंने हाशिये पर रख दिया है□ इसकी पटकथा श्रीलंका की जमीन पर लिखी जा रही है□ श्रीलंका के थिंक टैंक ने सवाल उठाया है कि जब तमिलों के संहार के लि□ महिंदा राजपक्षे को कठघरे में ख□ा किया जा सकता है, तो मोदी को क्यों नहीं? इस्लामाबाद भी, कोलंबो के इस सवाल से इत्तफाक रख रहा है□ श्रीलंका में अभी यह मामला थिंक टैंक, टीवी, अखबारों में बहस के स्तर पर है□ इसे सरकार के स्तर पर नहीं उठाया गया है□ '□शियन ह्यूमन राइट्स वाच' और 'वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स वाच' जैसी संस्था□ं क्यों इस सवाल को उठाने में योगदान दे रही हैं, जबकि उन्हें संस्था चलाने के लि□ पैसा यूरोप से मिलता है□ खैर, किसी का धंधा तो चाहि□ ही□

यूरोप वाले इस समय भावी सरकार से भय और प्रीत का कूटनीतिक कार्ड खेल रहे हैं□ पिछले तीन महीनों में यूरोप के व्यापारिक और कूटनीतिक समूहों ने सबसे अधिक भारत की यात्रा की है□

दो मई को ही पांचवें 'इयू-इंडिया फोरम' की दो दिवसीय बैठक नई दिल्ली में हुई, उसमें भावी सरकार से रणनीतिक भागीदारी पर चर्चा हुई□ इसके हफ्ते भर के भीतर, ब्रसेल्स स्थित इयू-इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स (इआइसीसी) और यूरोपियन बिजनेस ऐंड टेक्नोलॉजी सेंटर (इबीटीसी) ने नई दिल्ली में □क रिपोर्ट जारी की, जिसमें यूरोपीय कंपनियों की भारत में सक्रियता पर विस्तार से चर्चा की गई□

इन दो ब□ आयोजनों के वक्त को लेकर सवाल तो बनता है कि आखिर यूरोप वालों को भारत में निवेश को लेकर इतनी बेचैनी क्यों है□ इस मंच पर भारत के खुदरा व्यापार में विदेशी कंपनियों की भागीदारी की पुरजोर वकालत करते हु□ उद्योगपति संजय डालमिया ने कहा कि विदेशी पूंजी निवेश से अगर रोजगार के अवसर ब□ हैं, तो खुदरा व्यापार में निवेशकों को प्राथमिकता देने में हर्ज क्या है□

इसी मंच पर इआइसीसी के महासचिव सुनील प्रसाद ने यूरोप-भारत के बीच फ्री ट्रेड □ग्रीमेंट (□फटी□) व ब्राड बेस्ट ट्रेड □ंड इंवेस्टमेंट □ग्रीमेंट (बिटिया) पर हस्ताक्षर नहीं कि□ जाने को लेकर सवाल उठाया□ सुनील प्रसाद ने कहा कि 2007 से बातचीत चल रही है, पर अब तक 'बिटिया' की 'शादी' नहीं हुई□ '□फटी□ और बिटिया' □क ऐसा उदाहरण है, जो यूरोपीय लालफीताशाही और उसकी धीमी गति को रेखांकित करता है□

भारत और यूरोपीय संघ, इस समय कई बातों में □क दूसरे को करीब पाते हैं□ यूरोपीय संघ अट्ठाईस देशों का संगठन है, और भारत में भी अट्ठाईस राज्य हैं□ भारत में चुनाव के साथ-साथ, यूरोपीय संसद का चुनाव इस माह हो रहा है□ सोलह मई को भारत में चुनाव परिणाम आ जा□गा, उसके दस दिन बाद 751 सदस्यीय यूरोपीय संसद के चुनाव के नतीजे सामने होंगे□ 2009 में यूरोपीय संसद के चुनाव में तैंतालीस प्रतिशत से भी कम मतदाताओं ने वोट डाले थे□ अब भारतीय मतदाताओं की हिस्सेदारी को उदाहरण के तौर पर यूरोप में पेश किया जा रहा है□ भारत में इस समय 'सेंटर-राइट' (दक्षिणपंथी मध्यमार्गी) राजनीति के सत्ता में आने की हवा बन रही है, यही हाल यूरोप का है□

यूरोपीय संसद में सेंटर राइट वाले सत्ता में आ जा□ं, इसके लि□ पूरा माहौल बनाया गया है□ इयू चुनाव में लक्जमबर्ग के पूर्व प्रधानमंत्री और सेंटर राइट के नेता ज्यों क्लाउडे यूंकर, 'पैन यूरोपियन पार्टी ग्रुप' के कारण आगे चल रहे हैं□ क्या सेंटर राइट नेता यूंकर, जर्मनी के मार्टिन शुल्ज जो ईयू के मौजूदा प्रेसिडेंट अध्यक्ष हैं, की कुर्सी छीन पा□ंगे? यह कौन बनेगा करो□पति जैसा सवाल है□ शुल्ज, यूरोपीय संसद में सेंटर लेफ्ट (मध्य-वाम) का प्रतिनिधित्व करते हैं□ भारत की तरह यूरोपीय राजनीति में भी, □क पल में हवा का रुख बदलने की स्थिति बनी हुई है□

लक्जमबर्ग स्थित सांख्यिकी जानकारी देने वाली संस्था 'यूरोस्टाट' के ब्योरे पर भरोसा करें तो यूरोपीय संघ, सन दो हजार से अब तक 48.7 अरब यूरो का निवेश भारत में कर चुका है□

यूरोपीय संघ भारत में सबसे अधिक निवेश करने वाला समूह है, फिर भी मुक्त व्यापार समझौता (□फटी□ या बटिया) नहीं हो पा रहा है□ क्या लिस्बन करार की वजह से ऐसा हो रहा है? 1 दिसंबर 2009 से लागू लिस्बन समझौते की शर्तें इतनी कड़ी हैं कि सात वर्षों से □फटी□ का समाधान नहीं हो पा रहा है□ फिर भी '□फटी□' और 'बटिया' के बगैर भारत-यूरोप के बीच व्यापार हो रहा है□ 2012 में भारत-यूरोपीय संघ के बीच तिरसठ सौदे हु□ थे, लेकिन 2013 में सिर्फ इकतालीस सौदे हो पा□□ ईयू-इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स (इआइसीसी) और यूरोपियन बिजिनेस ऐंड टेक्नोलॉजी सेंटर (इबीटीसी) के प्रतिनिधियों ने नई दिल्ली में रिपोर्ट जारी करते वक्त इस पर चिंता व्यक्त की, और कहा कि उसके लि□ खुदरा व्यापार में निवेश को रोकने, और यहां की लालफीताशाही दोषी है□

'□फडीआइ इंटेलीजेंस' के सूत्र बताते हैं कि 2004 से 2013 तक यूरोप की 2566 परियोजना□ं भारत में कार्यरत रही हैं, जिनसे करीब पांच लाख बासठ हजार रोजगार के अवसर मिले हैं□ इतने रोजगार देने में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की ब□ी भूमिका रही है□

इन तीन देशों की रोजगार सृजन में इक्यावन प्रतिशत हिस्सेदारी रही है□ पर अकेले अमेरिका ने पिछले दस वर्षों की अवधि में यूरोप से कहीं अधिक, पांच लाख, पचिहत्तर हजार सात सौ ग्यारह न□ रोजगार भारत में दि□, और जापान ने करीब दो लाख पच्चीस हजार काम के अवसर यहां पर दि□□ क्या यूरोपीय संघ, अमेरिका और जापान जैसे देश, भारत में रोजगार देने का सवाल उठा कर नई सरकार पर खुदरा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लि□ दबाव बना□ंगे?

भारत में शिक्षा का □क ब□ा उद्योग बन चुका है□ यूरोपीय-अमेरिकी कंपनियां भारत में निजी विश्वविद्यालयों की बा□ लाने को लालायित हैं□ 2012 में आइआइ□म (अमदाबाद) के □क शोध में पता चला कि विदेश जाकर प□ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में 256 प्रतिशत की वृद्धि हुई है□ □सोचैम का आकलन है कि इससे तेरह अरब डॉलर का सालाना नुकसान भारत को हो रहा है, इसलि□ 2020 तक भारत में सा□ चार करो□ छात्रों को उच्च शिक्षा देने के लि□ आठ सौ विश्वविद्यालय और चाहि□□ ऑटोमोबाइल, संरचना, रियल इस्टेट, खाद्य प्रस्संकरण, ऊर्जा, सैन्य साजो- सामान, तकनीक मीडिया-टेलीकम्युनिकेशन (टी□मटी) में निवेश के लि□ यूरोप नई सरकार से सुविधा□ं चाहता है□ पिछले तीन महीने से यूरोप वाले जिस तरह से रणनीतिक बातचीत कर रहे हैं, उससे इसकी झलक मिलती है□

राजनीतिक नारों से पक चुकी जनता के लि□ सोलह मई के बाद महत्त्वपूर्ण यह नहीं रह जा□गा कि सरकार किसने बना ली है□ महत्त्वपूर्ण यह होगा कि नई सरकार के सरोकार क्या हैं□ और जो निवेश करने वाले बाहरी देश हैं, अगर उनकी बातें अनसुनी होती हैं, तो यहां पूंजी लगाने वाले देशों की सरकारें कम से कम 'दंगा स्मारक' बनाने की पहल तो करेंगी ही!

फेसबुकपेज को लाइककरने केलि क्लिककरें- https://www.facebook.com/Jansatta

ट्वटिर पेज पर फॉलो करने केलि क्लिककरें- https://twitter.com/Jansatta